राम चंद गुप्ता, जे के समक्ष।

नायब सिंह व *अन्य-अपीलकर्ता*

बनाम

गुरदेव *कौर - प्रतिवादी*

1984 का आर.एस.ए. संख्या 3174

18 अप्रैल, 2011

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-धारा 100-द्वितीय अपील केवल तभी बनाए रखने योग्य है जब कानून का पर्याप्त प्रश्न शामिल हो- वसीयत - वादी ने लाभार्थी के पक्ष में पंजीकृत वसीयत निष्पादित की जो विधवा-वादी के साथ रहती थी और उसकी भूमि की देखभाल करती थी - धोखाधड़ी और गलत बयानी द्वारा लाभार्थी ने अपनी निरक्षरता का लाभ उठाते हुए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को भी निष्पादित किया। इसके बाद, वादी ने इस तथ्य के कारण अपनी वसीयत रद्द कर दी कि लाभार्थी उसे परेशान कर रहा था- कथित जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर लाभार्थी ने वादी की पूरी जमीन बेच दी - वादी ने घोषणा और संयुक्त कब्जे के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया जिसमें बिक्री विलेख और जमीन पर उत्परिवर्तन को चुनौती दी गई और बेची गई एक दिखावा और अवैध लेनदेन होने के नाते- ट्रायल कोर्ट द्वारा

मुकदमा खारिज कर दिया गया- अपील की अनुमति दी गई जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी धोखाधड़ी का परिणाम है - नियमित दूसरी अपील निचली अदालत के फैसले और डिक्री को बरकरार रखते हुए खारिज कर दिया।

कहा गया है कि वर्तमान अपीलकर्ता-प्रतिवादियों के पिता द्वारा प्रतिवादी-वादी पर धोखाधड़ी की गई है, स्पष्ट है। इसे साबित करने के लिए प्रतिवादी-वादी द्वारा किसी अन्य साक्ष्य का नेतृत्व करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गवाह झूठ बोल सकते हैं लेकिन हालात नहीं। यह अपीलकर्ता-प्रतिवादियों के लिए था कि वे धोखाधड़ी, गलत बयानी या अनुचित प्रभाव की अनुपस्थिति को साबित करें क्योंकि उनके पिता एक प्रमुख स्थिति में थे, अर्थात-प्रतिवादी-वादी, जो एक अनपढ़ महिला थी। यह अपीलकर्ता-प्रतिवादियों के लिए था कि यह साबित करें कि लेनदेन में निष्पक्ष खेल था और यह लेनदेन वास्तविक और *सदाशय* है।

(पैरा 25)

आगे कहा गया है कि आमतौर पर, एक व्यक्ति, जो धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव आदि के आधार पर लेनदेन की वैधता को चुनौती देता है और अपने प्रतिद्वंद्वी पर बुरे विश्वास का आरोप लगाता है और विशेष रूप से जब लेनदेन पंजीकृत दस्तावेज होता है, तो सबूत का बोझ उस पर होता है और हालांकि, जब प्रत्ययी संबंध के अस्तित्व के कारण उनमें से एक अनुचित प्रभाव डालने

की स्थिति में होता है, या दूसरे पर प्रभुत्व रखता है और उससे कोई लाभ लेता है, तो लेनदेन के अच्छे विश्वास को प्रदान करने का बोझ प्रमुख पार्टी पर डाल दिया जाता है।

(पैरा 26)

आई.आई.आर. भारद्वाज, अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता।

अशोक सिंगला अधिवक्ता, - प्रतिवादी के लिए

राम चंद गुप्ता जे.

1. वर्तमान नियमित द्वितीय अपील के तथ्य इस प्रकार हैं:-

2. संत सिंह (मृतक) का वादपत्र के शीर्षक में वर्णित कुल भूमि में आधा हिस्सा था। मुकदमा दायर करने से लगभग 35-36 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई और वे अपने पीछे दो विधवाएँ, श्रीमती शांति- वादी और श्रीमती चोट्टो छोड़ गए। मूल रूप से यह मुकदमा मृतक संत सिंह की विधवा श्रीमती शांति द्वारा 9.5.1979 को एक निर्धन व्यक्ति के रूप में दायर किया गया था। श्रीमती शांति की मृत्यु के बाद, गुरदेव कौर को गुरदेव कौर के

पक्ष में श्रीमती शांति द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 6.2.1979, Ex.A-1 के आधार पर उनके कानूनी प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया था। गुरदेव कौर को एक निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की भी अनुमति दी गई। जैसा कि वादपत्र के शीर्षक में बताया गया है, श्रीमती शांति के पास कुल 192 कनाल 3 मरला भूमि में 1/4 हिस्सा था। श्रीमती परसीन कौर संत सिंह की एक और विधवा श्रीमती छोटो की बहन हैं। हरचरण सिंह परसीन कौर के पति हैं। अपीलकर्ता-प्रतिवादी नायब सिंह, गुरमेल सिंह और जगदेव सिंह हरचरण सिंह और पारसीन कौर के बेटे हैं। संत सिंह की मृत्यु के बाद, हरचरण सिंह, संत सिंह की दोनों विधवाओं श्रीमती शांति और श्रीमती छोटो के साथ रहने लगे और उनकी जमीन की देखभाल करने लगे और उन दोनों का विश्वास जीत लिया। 1984 (O & M) -2 के नियमित द्वितीय अपील संख्या 3174 के हरचरण के अनुनय पर - सिंह, श्रीमती शांति और श्रीमती छोटो मनसा के पक्ष में अपनी संपत्ति की वसीयत निष्पादित करने के लिए उनके साथ गए। हरचरण सिंह के पिता वज़ीर सिंह और हरचरण सिंह के चाचा दरबारा सिंह भी उनके साथ थे।

3. श्रीमती शांति द्वारा स्थापित मामले के अनुसार, हालांकि वह और श्रीमती छोटू अपनी संपत्ति की वसीयत हरचरण सिंह के पक्ष में निष्पादित करना चाहते थे और वास्तव में, उन्होंने हरचरण सिंह के पक्ष में दिनांक 17.7.1967 की एक वसीयत निष्पादित की और पंजीकृत कराई और, हालांकि, इस तथ्य का अनुचित लाभ उठाते हुए कि वह एक अनपढ़ महिला थी और हरचरण

सिंह के प्रभाव में थी, जब वह एक होटल में बैठी थी, तो उसने उसे स्पष्ट किए बिना इस दलील पर कि वसीयत के निष्पादन के लिए उसके अंगूठे का निशान लिया जा रहा था, एक अन्य दस्तावेज़ पर उसके अंगूठे का निशान ले लिया। इसलिए उसने विल की तरह ही अपना अंगूठा लगा लिया। हालाँकि, वर्तमान मुकदमा दायर करने से एक साल पहले, हरचरण सिंह ने श्रीमती शांति को परेशान करना शुरू कर दिया था और उन्होंने उनकी जमीन का उचित रिटर्न देने से भी इनकार कर दिया था और इसलिए, उन्होंने 6.2.1979 को सब रजिस्ट्रार, बुढलाडा के कार्यालय का दौरा किया और दिनांक 17.7.1967 को हरचरण सिंह के पक्ष में निष्पादित की गई वसीयत को रद्द कर दिया और दूसरी वसीयत वर्तमान वादी गुरदेव कौर के पक्ष में निष्पादित की गई। हालाँकि, 20.3.1979 को श्रीमती शांति को हल्का पटवारी से पता चला कि हरचरण सिंह ने उनके साथ धोखाधड़ी करके उनसे और श्रीमती छोटो से मुख्तारनामा बनवा लिया है। आगे यह दलील दी गई है कि उक्त मुख्तारनामे, दिनांक 17.7.1967 के आधार पर, हरचरण सिंह ने 20.2.1979 को, यानी वसीयत रद्द करने के कुछ दिनों के बाद, अपने बेटों के पक्ष में श्रीमती शांति की पूरी संपत्ति का विक्रय विलेख निष्पादित किया। उनके पक्ष में और गुरदेव कौर के पक्ष में एक और वसीयत निष्पादित की, जो श्रीमती शांति की मां के पिता की बहन हैं। उक्त विक्रय-पत्र काल्पनिक है और बिना किसी प्रतिफल के है और यह अमान्य है और श्रीमती शांति के अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं है। म्यूटेशन संख्या 865, जिसे

उक्त विक्रय पत्र दिनांक 20.2.1979 के आधार पर स्वीकृत किया गया था, को भी चुनौती दी गई है। वादी ने स्वामित्व के आधार पर विवादित भूमि पर कब्जे का भी दावा किया, इस दलील पर कि मुख्तारनामा और उसके बेटों के पक्ष में हरचरण सिंह द्वारा बिक्री विलेख का निष्पादन धोखाधड़ी, अवैध और शून्य और एक दिखावटी लेनदेन का परिणाम है।

4. अपीलार्थी-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर मुकदमा लड़ा गया है कि मुख्तारनामा दिनांक 17.7.1979 को श्रीमती शांति ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से हरचरण सिंह, उनके पिता, जिन को श्रीमती शांति द्वारा किसी भी तरीके से संपत्ति से निपटने के लिए अधिकृत किया गया था, के पक्ष में निष्पादित किया था और वे हरचरण सिंह, श्रीमती शांति के जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर से `36,000/- के लिए वास्तविक खरीदार हैं, और इसलिए, यह निवेदन किया गया है कि श्रीमती शांति या गुरदेव कौर को उनसे विवाद में भूमि का कब्ज़ा मांगने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात से इनकार किया जाता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी धोखाधड़ी और गलत बयानी का परिणाम है। इस बात से भी इनकार किया गया है कि श्रीमती शांति के अटॉर्नी के रूप में उनके पिता हरचरण सिंह द्वारा उनके पक्ष में किया गया विक्रय-पत्र एक दिखावटी लेनदेन है।

5. पक्षों की दलीलों से, निम्नलिखित मुद्दों को निर्णय के लिए विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किया गया: -

1. क्या वाद वर्तमान स्वरूप में चलने योग्य नहीं है। ओपीडी
2. क्या वादी को मुख्तियार-नामा दिनांक 17.7.1967 को चुनौती देने से रोका गया है? ओपीडी.
3. क्या हरचरण सिंह के गैर-ज्वाइन्डर के लिए मुकदमा खराब है? ओपीडी.
4. क्या न्यायालय शुल्क और क्षेत्राधिकार के प्रयोजनों के लिए मुकदमे का उचित मूल्य निर्धारण किया गया है? ओपीपी.
5. क्या कथित धोखाधड़ी के विवरण के अभाव में वादपत्र दोषपूर्ण है? ओपीडी.
6. क्या प्रतिवादी वाद भूमि में किसी अन्य के अधिकार की सूचना के बिना मूल्य के लिए वास्तविक क्रेता हैं और उनके पक्ष में बिक्री सुरक्षित है? ओपीडी
7. क्या मुख्तियारनामा दिनांक 17.7.1967 को श्रीमती शांति द्वारा हरचरण सिंह के पक्ष में निष्पादित किया जाना धोखाधड़ी और गलत बयानी का परिणाम है? ओपीपी
8. क्या प्रतिवादी संख्या 1 से 3, जो हरचरण सिंह के पुत्र हैं, के पक्ष में 1/4वें हिस्से के संबंध में श्रीमती शांति के मुख्त्यार द्वारा दिनांक 20.2.1979 को निष्पादित विक्रय-पत्र शून्य और अवैध है और धोखाधड़ी का परिणाम है और इससे वाद भूमि में श्रीमती शांति के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? ओपीपी.

9. क्या मुकदमा समय के भीतर है? ओपीपी.

10.क्या वादी वाद की भूमि पर कब्ज़ा पाने का हकदार है? ओपीपी.

11.राहत।"

6. पक्षों ने विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपने संबंधित तर्कों के समर्थन में मौखिक और साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। चूंकि श्रीमती शांति की मृत्यु गवाह बॉक्स में आने से पहले ही हो गई थी, इसलिए, उनके कानूनी प्रतिनिधि, श्रीमती गुरदेव कौर ने खुद को PW 1 के रूप में जांचा, जबकि उत्तरदाताओं-प्रतिवादियों में से एक नायब सिंह ने खुद को DW 1 के रूप में जांचा। DW2 गुरचरण सिंह सोदी, डीड राइटर हैं। DW3 का नाम मनसा सिंह, लंबरदार है, DW4 का नाम दरबारा सिंह है और DW5 का नाम हरचरण सिंह है, जो प्रतिवादियों के पिता हैं।

Ex.P1 वर्ष 1977-78 की जमाबंदी की प्रतिलिपि है। Ex.D1 दिनांक 20.2.1979 का विक्रय विलेख है। Ex.D2 दिनांक 17.7.1967 की पावर ऑफ अटॉर्नी है।

7. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुद्दा संख्या 7, 8 और 10 का फैसला वादी के खिलाफ और मुद्दा संख्या 9 का फैसला उसके पक्ष में किया, जबकि

मुद्दा संख्या 2, 4, 5 और 6 का फैसला प्रतिवादियों-प्रतिवादियों के पक्ष में किया गया और मुद्दा अंक क्रमांक 1 और 3 उनके विरुद्ध। विभिन्न मुद्दों पर निष्कर्षों के परिणामस्वरूप, प्रतिवादी-वादी द्वारा दायर मुकदमा खारिज कर दिया गया।

8. उक्त फैसले के खिलाफ व्यथित होकर, प्रतिवादी-वादी ने विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बठिंडा के समक्ष अपील दायर की, जिन्होंने उसके द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जबकि मुद्दा संख्या 5 से 8 और 10 पर निष्कर्ष को उलट दिया और इसके परिणामस्वरूप, प्रतिवादी- वादी को मुकदमे की भूमि पर कब्ज़ा करने का हकदार माना गया, अर्थात, कुल 192 कनाल 3 मरल भूमि का 1/4 हिस्सा और, तदनुसार श्रीमती शांति द्वारा दायर मुकदमा, जिसका प्रतिनिधित्व अब श्रीमती गुरदेव कौर द्वारा किया जाता है, प्रतिवादी-वादी को ग्राम चक अली शेर में स्थित कुल 192 कनाल 3 मरला भूमि में से 1/4 हिस्से का संयुक्त रूप से कब्ज़ा, जो वादपत्र के हेडनोट में पूरी तरह से वर्णित है का आदेश दिया गया था ।

9. विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बठिंडा, दिनांक 19.10.1984 द्वारा पारित उक्त निर्णय और डिक्री के खिलाफ अपीलकर्ता-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा वर्तमान नियमित दूसरी अपील दायर की गई है, जिसे 11.3.1985 को कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए बिना इस न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया था।

10. घनपत बनाम राम देवी[1] के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने यह विचार किया था कि पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 41 के मद्देनजर , नागरिक संहिता की धारा 100 के संशोधित प्रावधान 1976 में संशोधित प्रक्रिया, इस न्यायालय में दायर की गई दूसरी अपीलों पर लागू नहीं थी और तदनुसार, कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार नहीं किया गया था, न ही उपरोक्त नियमित दूसरी अपील कानून के ऐसे किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर स्वीकार किया गया। हालाँकि, कुलवंत कौर बनाम गुरदयाल सिंह मान (मृत)[2] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन के बाद वर्ष 1976, इस प्रकार धारा 100 में संशोधन करते हुए, पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 41 केंद्रीय अधिनियम, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता के लिए निरर्थक और प्रतिकूल हो गई थी और इसलिए इसे नजरअंदाज किया जाना था और इसलिए, दूसरी अपील केवल इस अदालत में संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 में कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर होगी ।

11. यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि यद्यपि वर्तमान अपीलों को स्वीकार करते समय कानून का प्रश्न तैयार नहीं किया गया था, और फिर भी, इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दयाल सरूप बनाम ओम प्रकाश (मृतक

[1] AIR 1978 (PB & Hy.) 137 (FB).
[2] JT 2001 (4) SC 158= AIR 2001 SC `1273

के बाद से) एल आरएस और अन्य[3] के माध्यम से देखा गया कि यह न्यायालय यहां तक कि अपील के आधारों में संशोधन किए बिना भी अपील की सुनवाई से पहले किसी भी समय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत कानून का प्रश्न तैयार कर सकता है। यह भी माना गया है कि संहिता की धारा 100(4) और 100(5) के तहत अपील की सुनवाई करते समय कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करना न्यायालय का कर्तव्य है और कानून के प्रश्न को कार्यवाही की किसी भी स्तर पर उठाने की अनुमति दी जा सकती है।

12. इसलिए, इस कानूनी प्रस्ताव के मद्देनजर, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील को इस अपील में उत्पन्न होने वाले कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न दायर करने के लिए कहा गया था।

13. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने इस अपील में उत्पन्न होने वाले कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न दायर किए हैं: -

"a. क्या विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा की गई बिक्री को केवल इसलिए रद्द किया जा सकता है क्योंकि यह वकील/विक्रेता के निकट रिश्तेदार के पक्ष में है?

b. क्या प्रिंसिपल और वकील के बीच किसी अनधिकृत कार्य के लिए दायित्व स्वयं वकील के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित नहीं होगा और बिक्री

[3] 2010 (4) PLR 1

प्रभावित नहीं होगी जब अटॉर्नी की शक्ति स्पष्ट रूप से उसे अलगाव की शक्ति देती है?"

14. मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और पूरे रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

15. अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वे विचार के लिए वास्तविक खरीदार हैं और केवल इस आधार पर कि वे हरचरण सिंह के बेटे हैं, जिन्होंने फांसी दी थी विक्रय विलेख उनके पक्ष में है, यह नहीं कहा जा सकता कि विक्रय विलेख एक दिखावटी लेनदेन है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि हरचरण सिंह ने मृतक श्रीमती शांति द्वारा अपने पक्ष में सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी को विधिवत निष्पादित किया था और पावर ऑफ अटॉर्नी एक पंजीकृत थी और इसे हरचरण सिंह द्वारा अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादन की तारीख तक श्रीमती शांति द्वारा वापस नहीं लिया गया था। आगे यह तर्क दिया गया है कि चूंकि पावर ऑफ अटॉर्नी एक पंजीकृत है और इसलिए, पावर ऑफ अटॉर्नी पर उप रजिस्ट्रार का वैधानिक समर्थन यह स्थापित करता है कि वही उसे पढ़ा गया था और उसने सब रजिस्ट्रार के समक्ष इसे विधिवत समझने के बाद अपने अंगूठे का निशान लगाया था। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचकर अवैधता की है कि दस्तावेज़ की सामग्री के बारे में उसे बताए बिना उससे अंगूठा लगवा लिया गया था। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि यदि श्रीमती शांति

का अपने वकील, यानी, हरचरण सिंह के साथ कोई विवाद था, तो वह उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकती थी और उस आधार पर हरचरण सिंह द्वारा अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख को एक दिखावटी लेन-देन नहीं कहा जा सकता है। आगे यह तर्क दिया गया है कि धोखाधड़ी की दलील, आपराधिक अपराध के किसी भी अन्य आरोप की तरह, चाहे वह नागरिक या आपराधिक कार्यवाही में लगाई गई हो, उचित संदेह से परे स्थापित की जानी चाहिए और धोखाधड़ी का निष्कर्ष संदेह और अनुमानों पर आधारित नहीं हो सकता है। आगे यह तर्क दिया गया है कि श्रीमती शांति की मृत्यु गवाह बॉक्स में उपस्थित हुए बिना हो गई और इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि किन परिस्थितियों में, उन्होंने हरचरण सिंह के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की और इसलिए, यह तर्क दिया गया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को उलटने में अवैधता की है।

16. उन्होंने पुरजोर ढंग से तर्क दिया है कि यदि कोई दस्तावेज़ एक पंजीकृत दस्तावेज़ है, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र तब तक वास्तविक माना जाएगा जब तक कि इसके विपरीत कोई निर्विवाद सबूत पेश नहीं किया जाता है और उस पंजीकृत दस्तावेज़ को अनुमानों और अनुमानों पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस बिंदु पर उन्होंने संत राम बनाम बृज मोहन कौरा और

अन्य[4], चानन सिंह और अन्य बनाम मित सिंह और अन्य[5], राम चंद्र दास बनाम फ़र्ज़संद अली खान और अन्य[6] , ईश्वर दास जैन (मृत) एलआर के माध्यम से बनाम सोहन लाल (मृत) एलआर के माध्यम से [7], वोलेटी वेंकट रामाराव बनाम कासप्रगदा भास्कररराव और अन्य[8] , सुभाष चंद्र कुमार बनाम प्रभु दयाल और अन्य[9], श्रीमती रामी बनाम सोहन सिंह (मृतक)) और अन्य[10], शिवदास लोकनाथसिंग और अन्य बनाम गयाबाई शंकर सुरवासे[11], इरुदयम अम्मल और अन्य बनाम सलायथ मैरी[12] और राज कुमार और अन्य बनाम हरद्वारी और अन्य[13], में दिए गए कई निर्णयों पर भरोसा किया है ।

17. उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह वादी का काम था कि वह विशेष रूप से वर्तमान अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों के पक्ष में अटॉर्नी द्वारा सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी और बिक्री विलेख के निष्पादन में कथित धोखाधड़ी को साबित करे और साबित करे, हालांकि, प्रतिवादी-वादी विफल रहा है वही साबित करने के लिए. इस बिंदु पर, उन्होंने एएलएन नारायणन चेट्टियार और अन्य बनाम आधिकारिक असाइनी उच्च न्यायालय, रंगून और अन्य[14], और बिशुंडेव

[4] 2006 (2) RCR (Civil) 769
[5] 2010 (2) HLR 320
[6] 1912 ILR 253
[7] 2000 (1) RCR (Civil) 168
[8] AIR 1962 AP 29
[9] 1994 PLJ 443
[10] 1991 PLJ 587
[11] 1994 (Civil Court Cases 597 (Bom.))
[12] AIR 1973 Mad. 421
[13] 2007 (2) RCR (Civil) 123
[14] AIR 1941 PC 93

नारायण और अन्य बनाम सेओगेनी राय और अन्य[15], पर भरोसा जताया है। सुप्रीम कोर्ट 280.

18. दूसरी ओर, प्रतिवादी-वादी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में मामले की स्वीकृत परिस्थितियों से धोखाधड़ी साबित होती है। यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी-वादी एक अशिक्षित महिला थी और वर्तमान अपीलकर्ता-प्रतिवादियों के पिता हरचरण सिंह का उस पर प्रभाव था क्योंकि माना जाता है कि वह उसके पति की मृत्यु के बाद उसकी जमीन की देखभाल करता था और उसका विश्वास जीतने के बाद, वह अपने पिता और चाचा के साथ उसे इस दलील पर मनसा ले आया कि उसे उसके पक्ष में एक वसीयत निष्पादित करनी थी और उसी का अनुचित लाभ उठाते हुए, उसने पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित कर ली, जो संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हुई है। आगे तर्क दिया कि जब श्रीमती शांति ने उन पर विश्वास खो दिया और अपनी वसीयत रद्द कर दी, तो उसके कुछ दिनों बाद, उन्होंने बिना किसी प्रतिफल के अपने बेटों, जिनमें से दो भी नाबालिग थे, के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया और वह प्रतिफल विक्रय विलेख में उल्लिखित था। यह भी एक काल्पनिक मामला है, क्योंकि हरचरण सिंह के किसी भी बेटे यानी वर्तमान अपीलकर्ताओं के पास कोई आय नहीं थी। यह भी तर्क दिया गया है कि हरचरण सिंह द्वारा श्रीमती शांति को कुछ भी भुगतान नहीं

[15] AIR 1951 SC 280

किया गया था और इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि चूँकि श्रीमती शांति और हरचरण सिंह के बीच भरोसेमंद संबंध थे, इसलिए धोखाधड़ी और गलत बयानी की अनुपस्थिति को साबित करने का भार वर्तमान अपीलकर्ता-प्रतिवादी और उनके पिता, क्योंकि उनके पिता एक प्रभुत्वशाली स्थिति में थे।

19. विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मुद्दे क्रमांक 5 से 8 और 10 पर विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को उलटने के लिए निम्नलिखित ठोस कारण बताए हैं:-

"9. पेटेंट तथ्य यह है कि सुश्री सांती को अपने पति संत सिंह की मृत्यु पर 192 कनाल 3 मरला विवादित भूमि में एक चौथाई हिस्सा मिला, जो मुकदमा दायर करने से 35/36 साल पहले हुआ था। सुश्री छोटू थीं संत सिंह की एक और विधवा और उसके बहनोई हरचरण सिंह, संत सिंह की मृत्यु के बाद इन सह-विधवाओं के साथ रहने लगे। मुकदमा दायर करने से पहले 35/36 वर्षों तक, हरचरण सिंह अपनी बहन की जमीन की देखभाल कर रहे थे। सास और सुश्री शांति और वह एकमात्र पुरुष थे, जो उनके हितों की देखभाल करते थे। सुश्री शांति और सुश्री छोटो के लिए यह स्वाभाविक था कि वे अपना सारा विश्वास हरचरण सिंह पर रखें और जो कुछ भी उन्होंने कहा, उसे सच मानें वे सोच भी नहीं सकते थे कि हरचरण सिंह उनके विश्वास को धोखा दे सकता है और उनके साथ कोई धोखाधड़ी कर सकता है। दरबारा सिंह (DW4) ने जिरह में कहा कि सुश्री शांति उन दिनों हरचरण सिंह पर

भरोसा करती थीं और सुश्री शांति हरचरण सिंह की सलाह और इच्छा के अनुसार काम करती थीं।

हरचरण सिंह ने कहा कि सुश्री शांति एक अनपढ़ महिला थीं। अपनी याचिका में सुश्री शांति की दलील यह थी कि उन्हें और सुश्री छोटो को हरचरण सिंह ने अपनी संपत्ति की वसीयत करने के लिए राजी किया था, और इस उद्देश्य के लिए उन्हें जोरा सिंह और मंशा सिंह के साथ हरचरण सिंह मनसा ले गए थे और वहां उसे एक होटल में बिठाया गया और एक दस्तावेज पर उसके अंगूठे के निशान लिए गए, जिसे उसे पढ़ा नहीं गया था और यह दर्शाते हुए कि वह अपनी संपत्ति की वसीयत उसके नाम कर रही थी। इससे पहले कि वह गवाह-बॉक्स से इन तथ्यों का उत्तर दे पाती, शांति की मृत्यु हो गई। यह निर्विवाद है कि 17.7.67 को सुश्री शांति ने अपनी संपत्ति की वसीयत हरचरण सिंह को कर दी, और इसी तरह, सुश्री छोटू द्वारा उनके पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई। इन वसीयतों के निष्पादित होने से पहले ही, गुरचरण सिंह का लिखित बयान को साबित करता है कि हरचरण सिंह ने नाम परिवर्तन कराने के एकमात्र उद्देश्य के लिए सुश्री छोटू और सुश्री संटी से अलग मुख्तार-नामा प्राप्त किया था। उसकी संपत्ति स्वीकृत यह सच है कि हरचरण सिंह सुश्री शांति के विश्वासपात्र व्यक्ति थे, इसलिए वह उन्हें मुख्तारनामा दे सकती थीं। हालाँकि, तथ्य यह है कि 30/35 वर्षों तक, हरचरण सिंह अपने पक्ष में लिखित मुख्तियारनामा के बिना एमएसटी शांति की भूमि की देखभाल कर रहे थे और एक्स.डी2 के कथित निष्पादन के

बाद भी, यह साबित नहीं हुआ है कि उन्होंने ऐसा किया था। सुश्री शांति के मुख्तियार के रूप में उनकी भूमि को किसी भी तरीके से हस्तांतरित करने का कोई भी कार्य, सिवाय इसके कि जब उन्होंने 20.2.1979 को अपने बेटों के पक्ष में बिक्री-डीड Ex.D1 निष्पादित किया हो, यानी, उनकी वसीयत रद्द होने के 18 दिनों के बाद संत कौर द्वारा Ex.A-1, दिनांक 6.2.1979 द्वारा। यदि हरचरण सिंह को भूमि का प्रबंधन बटाई या चकोटा पर देकर करना था और ज्यादातर खुद को, जो वह 30/35 वर्षों से कर रहे थे, तो उनके लिए औपचारिक मुख्तियारनामा निष्पादित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कृपादृष्टि। विवादित मुख्तारनामा के संबंध में मुंशी के रजिस्टर में प्रासंगिक प्रविष्टि गुरुचरण सिंह (DW2) द्वारा क्रमांक 672 पर दर्ज की गई थी। इस मुख्तारनामे का तात्पर्य सुश्री छोटो और सुश्री शांति द्वारा एक साथ निष्पादित किया जाना है। हरचरण सिंह की सगी बहन होने के नाते श्रीमती छोटू से यह अपेक्षा की गई थी कि वह इस मुख्तारनामे को स्वीकार कर लेंगी। मुंशी की प्रविष्टि संख्या 672 के सामने निष्पादक के अंगूठे के निशान/अंगूठे के निशान के लिए बने कॉलम में केवल एक अंगूठे का निशान है और वह गुरचरण सिंह सोढ़ी का बयान है। उपरोक्त प्रविष्टि संख्या 672 के सामने एकमात्र अंगूठे का निशान सुश्री शांति या सुश्री छोटू का नहीं बताया गया है। गुरचरण सिंह (DW2) ने कहा कि प्रविष्टि संख्या 672 में यह उल्लेख नहीं है कि यह अंगूठे का निशान किसका है। प्रतिवादी-उत्तरदाताओं द्वारा प्रविष्टि संख्या 672 के अंगूठे के निशान की तुलना विल

एक्स.ए-1 दिनांक 6.2.1979 पर सुश्री शांति के अंगूठे के निशान से करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था या वसीयत जिसे सुश्री शांति ने स्वीकार किया था कि उसने पक्ष में निष्पादित किया था 17.7.67 को हरचरण सिंह की। 17.7.67 को हरचरण सिंह के पक्ष में छोटू द्वारा निष्पादित वसीयत से संबंधित मुंशी के रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या 670, लेकिन उस प्रविष्टि के खिलाफ भी एमएसटी के अंगूठे का निशान है। संटी को मुंशी द्वारा प्राप्त किया गया था और फिर उसे आउट कर दिया गया था। दोनों विधवाओं की वसीयत के निष्पादन और विवादित मुख्तियारनामा के निष्पादन से पहले भी हरचरण सिंह को एमएसटी से मुख्तारनामा मिला था। शांति और छोटो ने अपनी संपत्ति के म्यूटेशन को मंजूरी देने के एकमात्र उद्देश्य के लिए और उस मुख्तारनामा के संबंध में प्रविष्टि गुरुचरण सिंह सोढ़ी द्वारा अपने रजिस्टर में क्रम संख्या 669 पर की थी। जब तक वसीयत और मुख्तारनामा निष्पादित नहीं किया गया, तब तक यह समझ में नहीं आता कि निष्पादक की ओर से उत्परिवर्तन की मंजूरी के लिए कोई मुक्तारनामा कैसे हो सकता था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सुश्री शांति ने मुंशी के रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या 672 पर अंगूठे का निशान लगाया था, यह साबित नहीं हुआ है, जबकि, उनके अंगूठे के निशान सुश्री छोटो की वसीयत से संबंधित प्रविष्टि के विरुद्ध गुरचरण सिंह द्वारा भेदभावपूर्ण तरीके से प्राप्त किए गए थे। प्रविष्टि क्रमांक 668 और प्रविष्टि क्रमांक 669 भी। मुख्तारनामा Ex.D2 पर एक नज़र नग्न आंखों से दिखाती है कि उप-रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणीकरण के तहत निष्पादक

के अंगूठे के निशान उसी काले पैड के साथ हैं जिसके साथ उनके अंगूठे के निशान मुंशी द्वारा प्राप्त किए गए हैं, और मुंशी नहीं है यह अपेक्षा की जाती है कि वह उप-रजिस्ट्रार के समक्ष गया होगा और उसने अपनी जांच में इस तथ्य को नहीं बताया है। यद्यपि सब-रजिस्ट्रार के प्रमाणपत्र के नीचे निष्पादक और प्रमाणित करने वाले गवाहों के अंगूठे के निशान पर उनके नामों का उद्धरण तेजी से हाथ से लिखा गया प्रतीत होता है, फिर भी इस उद्धरण की दृश्य तुलना मुंशी द्वारा उनके नामों के उद्धरण के साथ करने पर, मुझे विश्वास हो गया है कि मुंशी ने निष्पादक और साक्ष्य देने वाले गवाहों के नाम एक ही काली स्याही और कलम से उद्धृत किए हैं। प्रासंगिक तथ्य यह भी है कि उप-रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र अलग-अलग लिखावट में है, संभवतः पंजीकरण क्लर्क द्वारा, हल्की काली स्याही में, जबकि उप-रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर हल्की नीली स्याही में हैं। 1984 (ओ एंड एम) - 11 के नियमित द्वितीय अपील संख्या 3174- निष्पादक और उप रजिस्ट्रार के प्रमाण पत्र के नीचे गवाहों के नाम उद्धृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्याही प्रमाण पत्र लिखने के लिए उपयोग की जाने वाली स्याही की तुलना में बहुत अधिक मोटी है और उपयोग की गई स्याही से मेल खाती है। मुख्तारनामा Ex.D2 की बॉडी राइटिंग में। इसलिए, सबसे संभावित तथ्य यह है कि मुख्तारनामा Ex.D2 के साथ-साथ उप-पंजीयक के प्रमाण पत्र के नीचे निष्पादक और गवाहों के अंगूठे के निशान, उप-पंजीयक के समक्ष दस्तावेज़ रखे जाने से पहले मुंशी द्वारा प्राप्त किए गए थे, और वह उप-

रजिस्ट्रार ने स्टाम्प के ऊपर केवल अपने हस्ताक्षर किये, अन्यथा पंजीकरण की कार्यवाही उनके द्वारा संचालित नहीं की गयी और पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया अव्यवस्थित प्रकृति की थी। यह परिस्थिति स्वाभाविक रूप से वादी-अपीलकर्ता के संस्करण को रंग देती है कि सुश्री शांति ने कभी भी मुख्तारनामा Ex.D2 को निष्पादित नहीं किया क्योंकि वह इसकी सामग्री से परिचित नहीं थीं और न ही उन्होंने पंजीकरण प्रक्रिया में भाग लिया था। मुझे लगता है कि इस अवलोकन को दो परिस्थितियों से समर्थन मिलता है, और वे यह हैं कि Ex.D2 पर सुश्री शांति के अंगूठे के निशान प्राप्त करने के बाद, जो उन्हें पढ़ा नहीं गया था, हरचरण सिंह ने कभी भी किसी भी स्थानांतरण को प्रभावित करके मुख्तार के रूप में कोई कार्य नहीं किया। उनकी जमीन या तो बिक्री या बंधक या पट्टे के माध्यम से थी, और इस तथ्य के बावजूद कि हरचरण सिंह और सुश्री शांति के बीच निश्चित मनमुटाव और रास्ते अलग हो गए थे, उन्होंने अपनी वसीयत दिनांक 6.2.1979 में मुख्तारनामे का कोई संदर्भ या विवादित उल्लेख नहीं किया। जब सुश्री शांति ने स्वेच्छा से दिनांक 17.7.67 की अपनी वसीयत रद्द कर दी, इस कारण से कि हरचरण सिंह ने उनका विश्वास खो दिया था, तो उन्होंने विवादित मुख्तारनामा रद्द कर दिया होगा यदि उन्हें पता था कि ऐसा कोई मुख्तारनामा उनके द्वारा जानबूझकर और स्वेच्छा से निष्पादित किया गया था। यह सच है कि धोखाधड़ी को संदेह से परे स्थापित किया जाना चाहिए और इसका पता लगाना संदेह और अनुमान पर आधारित नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसी

परिस्थितियां हैं जो पुरुषों की तुलना में अधिक जोर से बोलती हैं और संदेह से परे सच्चाई को उजागर करती हैं। वर्तमान मामले में, Ex.D2 का गवाह वजीर सिंह कोई और नहीं बल्कि हरचरण सिंह का पिता था, जबकि दरबारा सिंह ने स्वीकार किया कि वह हरचरण सिंह का चाचा है। जब उनके पिता और चाचा उनके साथ थे और सुश्री शांति जो कुछ भी निष्पादित करना चाहती थीं वह एक वसीयत थी, तो हरचरण सिंह के लिए मुख्तारनामा Ex.D2 पर सुश्री शांति जैसी अनपढ़ महिला के अंगूठे का निशान बिना पढ़े प्राप्त करना मुश्किल नहीं था। उसकी, मुंशी की मिलीभगत से और फिर इसे एक अधिकारी द्वारा पंजीकृत करना, जिसकी कार्यवाही उसके क्लर्क द्वारा उसकी जानकारी के बिना की गई प्रतीत होती है। प्रत्ययी संबंध में रहने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी देखभाल के लिए दिए गए हितों की रक्षा करे और न्यायालय ऐसे व्यक्तियों के बीच ऐसे सभी लेनदेन पर ईर्ष्यापूर्वक नजर रखता है ताकि संरक्षक अपने प्रभाव या अपने विश्वास का उपयोग उस व्यक्ति के खिलाफ या उसके नुकसान के लिए न कर सके जिसके खिलाफ वह दबदबे वाली स्थिति में है. जब ऐसा कोई संबंध दिखाया जाता है, तो कानून सब कुछ लेन-देन के विरुद्ध मान लेता है और विश्वास या विश्वास की स्थिति रखने वाले व्यक्ति पर यह दिखाने की जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि लेन-देन पूरी तरह से निष्पक्ष और उचित है और दूसरा व्यक्ति उस दस्तावेज़ का सचेत एजेंट था जिसका तात्पर्य है उसके द्वारा निष्पादित किया गया है। गुलजान बीबी बनाम नज़ीर-उद-दीन मिया, एआईआर 1975 गौहाटी 30, और राम कलाप पांडे वी. बंसीधर और अन्य, एआईआर 1947 अवध, 89

को इस प्रस्ताव पर लाभ के साथ संदर्भित किया जा सकता है। इस चर्चा में गिनाए गए तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, मुझे यकीन है कि श्रीमती शांति के बयान के बिना, जिनके साथ धोखाधड़ी की गई थी, हरचरण सिंह ने उनसे एक दस्तावेज़ पर उनके अंगूठे के निशान लेने के लिए धोखाधड़ी की थी, जो उनका मुख़्तारनामा निकला। वादी में शामिल इस धोखाधड़ी के विवरण पर्याप्त थे क्योंकि प्राकृतिक जीवन में, सुश्री शांति से उससे अधिक जानने की उम्मीद नहीं की गई थी कि उसने क्या निवेदन किया था और उसके कानूनी प्रतिनिधि ने वादी में क्या दोहराया है। मुद्दे संख्या 5 और 7 पर विद्वान परीक्षण न्यायाधीश के निष्कर्षों को उलट दिया गया है, और इन मुद्दों का निर्णय प्रतिवादियों-उत्तरदाताओं के खिलाफ और वादी-अपीलकर्ता के पक्ष में किया गया है।" नज़ीर-उद-दीन मिया, एआईआर 1975 गौहाटी 30, और राम कलाप पांडे वी. बंसीधर और अन्य, एआईआर 1947 अवध, 89 को इस प्रस्ताव पर लाभ के साथ संदर्भित किया जा सकता है। इस चर्चा में गिनाए गए तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, मुझे यकीन है कि श्रीमती शांति के बयान के बिना, जिनके साथ धोखाधड़ी की गई थी, हरचरण सिंह ने उनसे एक दस्तावेज़ पर उनके अंगूठे के निशान लेने के लिए धोखाधड़ी की थी, जो उनका मुख़्तारनामा निकला। वादी में शामिल इस धोखाधड़ी के विवरण पर्याप्त थे क्योंकि प्राकृतिक जीवन में, सुश्री शांति से उससे अधिक जानने की उम्मीद नहीं की गई थी कि उसने क्या निवेदन किया था और उसके कानूनी प्रतिनिधि ने वादी में क्या दोहराया है। मुद्दे

संख्या 5 और 7 पर विद्वान परीक्षण न्यायाधीश के निष्कर्षों को उलट दिया गया है, और इन मुद्दों का निर्णय प्रतिवादियों-उत्तरदाताओं के खिलाफ और वादी-अपीलकर्ता के पक्ष में किया गया है।" नज़ीर-उद-दीन मिया, एआईआर 1975 गौहाटी 30, और राम कलाप पांडे वी. बंसीधर और अन्य, एआईआर 1947 अवध, 89 को इस प्रस्ताव पर लाभ के साथ संदर्भित किया जा सकता है। इस चर्चा में गिनाए गए तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, मुझे यकीन है कि श्रीमती शांति के बयान के बिना, जिनके साथ धोखाधड़ी की गई थी, हरचरण सिंह ने उनसे एक दस्तावेज़ पर उनके अंगूठे के निशान लेने के लिए धोखाधड़ी की थी, जो उनका मुख़्तारनामा निकला। वादी में शामिल इस धोखाधड़ी के विवरण पर्याप्त थे क्योंकि प्राकृतिक जीवन में, सुश्री शांति से उससे अधिक जानने की उम्मीद नहीं की गई थी कि उसने क्या निवेदन किया था और उसके कानूनी प्रतिनिधि ने वादी में क्या दोहराया है। मुद्दे संख्या 5 और 7 पर विद्वान परीक्षण न्यायाधीश के निष्कर्षों को उलट दिया गया है, और इन मुद्दों का निर्णय प्रतिवादियों-उत्तरदाताओं के खिलाफ और वादी-अपीलकर्ता के पक्ष में किया गया है।"

20. विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय के पैरा संख्या 12 में इसे निम्नानुसार देखा गया है: -

"12. 12.12.1979, 7.11.1981 और 12.12.1981 को दायर अपने तीन लिखित बयानों में, तीन प्रतिस्पर्धी उत्तरदाताओं ने स्पष्ट शब्दों में अनुरोध किया कि उनके द्वारा एमएसटी शांति के हरचरण सिंह मुख्तारनामा को 36,000/- रुपये का भुगतान किया गया था। उन्होंने कभी यह दलील नहीं दी कि उन्होंने एमएसटी शांति को बिक्री मूल्य या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान कर दिया है। यह भी उनका तर्क नहीं था कि नायब सिंह ने समझौता किया था विक्रय-पत्र के निष्पादन से पांच दिन पहले सुश्री शांति के साथ विवादित भूमि की खरीद के लिए या कि हरचरण सिंह ने सुश्री शांति के निर्देशों के तहत उनके पक्ष में बिक्री-पत्र निष्पादित किया था। न ही उन्होंने अपने लिखित बयानों में यह दलील दी कि नायब सिंह ऐसे किसी भी बिक्री समझौते के समय सुश्री शांति को उनके घर पर 36,000/- रुपये का भुगतान किया गया था। उनके द्वारा दलील दी गई थी कि मुख्तारनामा दिनांक 17.7.67 के तहत, हरचरण सिंह को बिक्री-पत्र को प्रभावित करने का अधिकार था और वह वे उससे वास्तविक खरीदार हैं और उन्होंने पूरी बिक्री कीमत हरचरण सिंह मुख्तार-ए-आम को भुगतान की थी। बिक्री के निष्पादन से पांच दिन पहले नायब सिंह (DW1), मंशा सिंह (DW3) और हरचरण सिंह (DW5) द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य- विलेख के अनुसार, नायब सिंह ने सुश्री शांति के साथ बिक्री समझौते का लेन-देन किया था और उस समय, उनके घर पर उन्हें 36,000/- रुपये का नकद भुगतान किया था, और हरचरण सिंह ने सुश्री शांति के निर्देशों के तहत बिक्री-पत्र निष्पादित किया था। .सैंती

को उनके लिखित बयानों में दलील के अभाव के कारण विचार से बाहर किया जाना चाहिए। सुश्री शांति 40/50 वर्षों से एक अनपढ़ विधवा थीं और हरचरण सिंह उनसे दस्तावेज निष्पादित करवा रहे थे, लेकिन यह अजीब है कि उन्होंने कभी नहीं पूछा और न ही उनके बेटों ने सुश्री शांति से मुकदमे की जमीन के संबंध में किसी भी बिक्री-समझौते को निष्पादित करने की मांग की और न ही उन्होंने उससे 36,000/- रुपये के भुगतान की रसीद की मांग की। मंशा सिंह और ज़ोरा सिंह, जो Exh.D-1 के गवाह हैं, हरचरण सिंह के चचेरे भाई हैं और उनसे उनके पक्ष में कुछ भी गवाही देने की उम्मीद की जा सकती है। एमएसटी द्वारा संभावित मुकदमे के डर से हरचरण सिंह और उनके बेटे बिक्री पर प्राप्त विचार और भुगतान के अपने संस्करण पर अड़े नहीं हैं के लिए शांति - उससे बिक्री प्रतिफल की वसूली और उन्होंने अदालत में जो बताने की कोशिश की है, वह कुछ ऐसा है, जिसकी उन्होंने कभी पैरवी नहीं की है। उप-रजिस्ट्रार के समक्ष बिक्री प्रतिफल का कोई भी हिस्सा भुगतान नहीं किया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि हरचरण सिंह ने बिक्री-विलेख Exh.D-1 के निष्पादन के लिए वास्तव में कोई विचार किए बिना विवादित भूमि का कब्जा अपने बेटों को हस्तांतरित कर दिया है। इस सन्दर्भ में ज्ञातव्य है कि नायब सिंह की उम्र 20-09-1979 को लगभग बीस वर्ष थी, जबकि उनके दो भाई अभी नाबालिग हैं। उनके पास बिल्कुल भी जमीन या कोई अन्य संपत्ति नहीं थी, जिससे बिक्री पर 36,000/- रुपये का भुगतान किया जा सके। नायब सिंह

ने यह बताने की कोशिश की कि उनकी मां के पास कुछ जमीन थी, लेकिन यह तथ्य रिकॉर्ड पर साबित नहीं हुआ है। नायब सिंह की मां यह बताने नहीं आई थी कि उसके पास रुपये हैं। उनके बेटों को 36,000/- रुपये दिए जाएंगे। हरचरण सिंह ने यह बताने की कोशिश की कि उनकी पत्नी और बेटे उनसे अलग रहते थे, लेकिन इस कथन को मंशा सिंह ने झुठला दिया, जिन्होंने कहा कि हरचरण सिंह की पत्नी उनके साथ रहती थीं। इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि नायब सिंह और उसका नाबालिग भाई, जिनके पास बिल्कुल भी जमीन या संपत्ति नहीं है, अपने माता-पिता से अलग रह रहे हैं। वास्तव में, उनके पास ऐसा कोई स्रोत नहीं था जिससे Exh.D-1 में बताई गई कीमत का भुगतान किया जा सके। उन्होंने हरचरण सिंह को बिक्री प्रतिफल के भुगतान के संबंध में झूठी दलील दी, जिसे उन्होंने सुश्री शांति को भुगतान में से एक में बदलने की कोशिश की। इससे यह भी प्रतीत होता है कि 36 रुपये की बिक्री पर विचार, तथ्यों की प्रासंगिकता के बिना 000/- निर्धारित किया गया है। 192 कनाल 3 मरले में शांति का हिस्सा एक चौथाई है और यह लगभग 48 कनाल होता है, जिसमें से आधा नेहरी गुणवत्ता का है और आधा बरानी गुणवत्ता का है। हो सकता है कि गुरदेव कौर ने कोई लेन-देन न किया हो या कोई बिक्री न देखी हो, लेकिन उत्तरदाताओं के इस साक्ष्य से सहमत होने का कोई आधार नहीं है कि 6,000/- रुपये का बाजार मूल्य था। इन दिनों में, तीन किला नेहरी भूमि

और तीन किला बरनी भूमि 36,000/- रुपये में नहीं खरीदी जा सकती, सिवाय इसके कि जब बिक्री घरेलू मामला हो, जैसे Exh.D1 दिनांक 20-03-1979। सेल-डीड Exh.D1 के बिना होने के कारण विचार शून्य है और यह हरचरण सिंह और उनके बेटों के बीच एक अनपढ़ बूढ़ी विधवा को उस चीज़ से वंचित करने की मिलीभगत का परिणाम है जिस पर वह उसकी सांस और रोटी निर्भर थी।

वादी-अपीलकर्ता ऐसी बिक्री से बाध्य नहीं है। मुद्दे संख्या 6 और 8 पर विद्वान ट्रायल जज के निष्कर्षों को भी उलट दिया गया है, और जबकि मुद्दा नंबर 6 प्रतिवादियों - उत्तरदाताओं के खिलाफ तय किया गया है, मुद्दा नंबर 8 का फैसला वादी-अपीलकर्ता के पक्ष में किया गया है।"

21. जहां तक अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील के तर्क का सवाल है कि धोखाधड़ी, गलत बयानी या अनुचित प्रभाव का आरोप लगाने वाले पक्ष को विशेष रूप से दलील देनी होगी और इसे साबित करना होगा और जहां तक उपरोक्त अधिकारियों के पास कानूनी प्रस्ताव है, जिस पर विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया है। जहाँ तक अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों का सवाल है, कोई विवाद नहीं है। हालाँकि, कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के साथ भरोसेमंद रिश्ते में होता है और बाद में विश्वास की स्थिति में होता है, तो धोखाधड़ी, गलत बयानी या अनुचित प्रभाव की अनुपस्थिति को साबित करने का बोझ प्रभुत्व की स्थिति में व्यक्ति पर होता है और उसे साबित करना होता है लेन-देन में निष्पक्षता थी और लेन-

देन वास्तविक और प्रामाणिक है। इस दृष्टिकोण के लिए गुलजान बीबी बनाम नज़ीर-उद्दीन मिया[16], पर भरोसा किया गया है, जिसका प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है: -

"14. जब किसी मुकदमे में किसी पक्ष द्वारा धोखाधड़ी, गलत बयानी या अनुचित प्रभाव का आरोप लगाया जाता है, तो आम तौर पर, ऐसी धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव या गलत बयानी को साबित करने का बोझ उस पर होता है। लेकिन, जब कोई व्यक्ति दूसरे और बाद वाले के साथ विश्वासपूर्ण रिश्ते में होता है सक्रिय आत्मविश्वास की स्थिति में है, धोखाधड़ी, गलत बयानी या अनुचित प्रभाव की अनुपस्थिति को साबित करने का भार प्रभुत्वशाली स्थिति में बैठे व्यक्ति पर है; उसे यह साबित करना होगा कि लेनदेन में निष्पक्ष खेल था और जो स्पष्ट है वह वास्तविक है; दूसरे शब्दों में, लेन-देन वास्तविक और प्रामाणिक है। कानून प्रथम दृष्टया विधिवत निष्पादित कार्यों के पक्ष में मानता है। इसलिए, आमतौर पर एक व्यक्ति जो धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव आदि के आधार पर लेन-देन की वैधता को चुनौती देता है और आरोप लगाता है उनके प्रतिद्वंद्वी ने बुरे विश्वास के साथ, उस पर सबूत का बोझ डाला है। लेकिन, जहां प्रत्ययी संबंध के अस्तित्व के कारण उनमें से एक अनुचित प्रभाव डालने की स्थिति में है या दूसरे पर प्रभुत्व जमाता है और उससे कोई लाभ लेता है, तो लेन-देन की सद्भावना साबित करने का बोझ

[16] AIR 1975 (Gauhati) 30

प्रमुख पक्ष पर डाल दिया जाता है, यानी वह पक्ष जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में है। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रत्ययी संबंध में खड़े व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उसकी देखभाल के लिए दिए गए हितों की रक्षा करे और न्यायालय ऐसे व्यक्तियों के बीच सभी लेनदेन को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता है ताकि संरक्षक अपने लाभ के लिए अपने प्रभाव या विश्वास का उपयोग न कर सके। जब शिकायत करने वाला पक्ष इस तरह का संबंध दिखाता है, तो कानून सब कुछ लेन-देन के विरुद्ध मान लेता है और विश्वास या भरोसे की स्थिति रखने वाले व्यक्ति पर यह दिखाने की जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि लेन-देन पूरी तरह से निष्पक्ष और उचित है, कि उसकी स्थिति का कोई फायदा नहीं उठाया गया है। इस सिद्धांत को साक्ष्य अधिनियम की धारा 111 में शामिल किया गया है और मेरी राय में नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय यह मानने में सही थे कि यह धारा तत्काल मामले के तथ्यों पर लागू होती है।

22. इस बिंदु पर राम कलप पांडे बनाम बासीधर और अन्य[17], पर भी भरोसा किया जा सकता है, जिसके प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं: -

"7. जब लेन-देन के पक्ष समान स्तर पर खड़े नहीं होते हैं, तो कानून एक उपयुक्त मामले में धोखाधड़ी का अनुमान लगाता है। उन व्यक्तियों को बाध्य करने के लिए, जिन्होंने अपने कृत्यों या अनुबंधों द्वारा, अपनी संपत्ति के बड़े

[17] AIR 1947 Oudh 89

हिस्से को खुद से अलग कर लिया है , एक स्वतंत्र और पूर्ण सहमति होनी चाहिए, और उन लेनदेन में जिनमें पार्टियों में से एक स्वतंत्र और स्वैच्छिक एजेंट नहीं है और वह जो करता है उसके आयात की सराहना करने में असमर्थ है, मुख्य तत्व जो अधिनियम को अपना बनाते हैं, वे चाहते हैं। तदनुसार, जब कोई व्यक्ति, जो अपनी मानसिक स्थिति, उम्र, कमजोरी या अन्य विशिष्ट परिस्थितियों के कारण स्वतंत्र विवेक का प्रयोग करने में असमर्थ है, को दूसरे द्वारा ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाता है जिससे उसे चोट लग सकती है, तो वह व्यक्ति को उसके अनुचित आचरण से कोई लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। जब इसके अलावा दो पक्षों में से एक दूसरे के साथ प्रत्ययी संबंध में होता है, तो स्वाभाविक रूप से एक द्वारा विश्वास जताया जाता है और उस विश्वास से जो प्रभाव बढ़ता है वह है दूसरे के पास है. यदि इस विश्वास का दुरुपयोग किया जाता है, और विश्वास करने वाले पक्ष की कीमत पर लाभ प्राप्त करने के लिए प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, तो प्रभाव के अचेतन दुरुपयोग के माध्यम से संपत्ति या किसी भी लाभ को प्राप्त करना गंभीरतम चरित्र की धोखाधड़ी का गठन करता है: केर ऑन फ्रॉड, एडन.6 के अनुसार , पृष्ठ 153 से 160। जैसा कि लॉर्ड किंग्सडाउन ने (1859) 7 एचएलसी 750 में पृष्ठ 779 पर देखा:

'यह सिद्धांत हर उस मामले पर लागू होता है जहां प्रभाव हासिल किया जाता है और उसका दुरुपयोग किया जाता है, जहां भरोसा जताया जाता है और

धोखा दिया जाता है।' (1888) 36 Ch.D.145 में लिंडले एलजे ने सिद्धांत को इस प्रकार समझाया:

'सिद्धांत की जांच होनी चाहिए।' तो फिर सिद्धांत क्या है? क्या लोगों को उनकी अपनी मूर्खता के परिणामों से बचाना सही और समीचीन है? या क्या उन्हें अन्य लोगों द्वारा पीड़ित होने से बचाना सही और समीचीन है? मेरी राय में अनुचित प्रभाव का सिद्धांत इन सिद्धांतों में से दूसरे पर आधारित है। समानता की अदालतों ने कभी भी दानदाताओं की मूर्खता, अविवेक या दूरदर्शिता की कमी के आधार पर उपहारों को रद्द नहीं किया है। न्यायालयों ने हमेशा ऐसे किसी भी क्षेत्राधिकार को अस्वीकार किया है (1807) 14 वेस। 273 स्वयं इस आशय का स्पष्ट प्राधिकार है। यह स्पष्ट रूप से मूर्खता, लापरवाही, फिजूलखर्ची और बुराई को प्रोत्साहित करने के लिए होगा यदि व्यक्तियों को वह संपत्ति वापस मिल सके जो उन्होंने मूर्खतापूर्वक छीन ली है..... दूसरी ओर लोगों को किसी भी तरह से दूसरों द्वारा मजबूर, धोखा देने या गुमराह होने से बचाने के लिए सभी कानूनों के सबसे वैध उद्देश्यों में से एक में अपनी संपत्ति से अलग होना।' उसी मामले में कॉटन एलजे ने कहा:

`मामलों की दूसरी श्रेणी में न्यायालय हस्तक्षेप करता है, न कि 1984 की इस आधार पर कि कोई गलत कार्य वास्तव में प्राप्तकर्ता द्वारा किया गया है, बल्कि सार्वजनिक नीति के आधार पर, और पार्टियों के बीच मौजूद संबंधों

और उससे उत्पन्न होने वाले प्रभाव का दुरुपयोग होने से रोकना।' लॉर्ड हैल्सबरी इस बिंदु पर अंग्रेजी कानून का सारांश देते हुए कहते हैं:

'मामलों की दो श्रेणियां हैं जिनमें अनुचित प्रभाव के आधार पर इक्विटी न्यायालयों द्वारा उपहारों को रद्द कर दिया जाता है; पहला जहां अदालत संतुष्ट हो गई है कि उपहार इस उद्देश्य के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से उपयोग किए गए प्रभाव का परिणाम है; दूसरे, जहां उपहार के निष्पादन के समय या उससे कुछ समय पहले दाता और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध ऐसे हों जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि प्राप्तकर्ता का दाता पर प्रभाव था। ऐसे मामले में अदालत उपहार को तब तक रद्द कर देती है जब तक कि यह साबित न हो जाए कि यह वास्तव में परिस्थितियों के तहत कार्य करने वाले दाता का सहज कार्य था, जिसने उसे एक स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करने में सक्षम बनाया और जो अदालत को यह मानने में उचित ठहराता है कि उपहार का परिणाम था दाता की इच्छा का निःशुल्क प्रयोग...

ऐसे मामलों में जहां इस तरह के रिश्ते का अस्तित्व दिखाया गया है, राहत चाहने वाले पक्ष को यह साबित नहीं करना है कि वास्तविक धोखाधड़ी या जबरदस्ती या यहां तक कि प्रत्यक्ष अनुनय को नियोजित किया गया था: उसे केवल गोपनीय संबंध के अस्तित्व को साबित करना है, और फिर जिम्मेदारी उस पर आ जाती है पार्टी यह साबित करने के संदेश को बरकरार रखना चाहती है कि संबंध द्वारा प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया गया था।' (खंड 15 हेल्सबरी के इंग्लैंड के नियम, पैरा 491 देखें)।

8. भारत में धारा 111, साक्ष्य अधिनियम, यह नियम बताता है कि 'जहां पार्टियों के बीच लेनदेन की सद्भावना का सवाल है, जिनमें से एक सक्रिय विश्वास की स्थिति में दूसरे के सामने खड़ा है, साबित करने का बोझ लेन-देन का अच्छा विश्वास उस पार्टी पर है जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में है।"

33. इसी तरह के तथ्यों पर इस न्यायालय ने बाज सिंह और अन्य बनाम श्रीमती गाजो और अन्य[18] में निम्नानुसार टिप्पणी की: -

"4. दोनों प्रतिवादी श्रीमती गेजो और श्रीमती मेजो अनपढ़ ग्रामीण महिलाएं हैं। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया कि उन्होंने जानबूझकर मुख्तियारनामा में बागीचा सिंह को उनकी संपत्ति को हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत करने वाला खंड दर्ज कराया था। इसके अलावा, ट्रायल कोर्ट ने इस पर भरोसा किया माउंट.जन बनाम माउंट.फज्जन और अन्य में भिड़े, जे. का निर्णय, एआईआर 1939 लाहौर 351, जहां पावर ऑफ अटॉर्नी में समान परिस्थितियों में एक समान खंड व्याख्या के लिए आया था और यह माना गया था कि अटॉर्नी का इरादा नहीं था संपत्ति को हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत किया जाए। अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा इसके विपरीत कोई निर्णय नहीं दिया गया। तदनुसार, अलगाव की शक्ति के निष्कर्ष की पुष्टि की जानी चाहिए।"

[18] 1988 (2) PLR 42

24. चलती देवी और अन्य बनाम राजिंदर कुमार और अन्य[19] में इस न्यायालय के एक अन्य फैसले में , गुलजान बीबी के मामले पर भरोसा करते हुए (सुप्रा), इसे निम्नानुसार देखा गया: -

"15. मैं गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सम्मानजनक सहमत हूं। वर्तमान मामले में, वादी श्रीमती चलती देवी एक अनपढ़ महिला है। दीना नाथ, जो पूरे मामले में धुरी हैं, प्रतिवादियों के पिता हैं। वह कोई और नहीं बल्कि वादी श्रीमती चलती देवी के मृत पति का भाई है। वह वादी नंबर 1 श्रीमती चलती देवी पर प्रभुत्व स्थापित करने की प्रत्ययी क्षमता रखता है। यह स्पष्ट है कि उसके पति की मृत्यु के तुरंत बाद, एक पारिवारिक समझौता होता है कथित तौर पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त समझौते को पार्टियों द्वारा प्रभावी नहीं किया गया है। इसलिए, प्रतिवादियों द्वारा एक और पारिवारिक समझौते पर भरोसा किया गया है जो इस मुकदमे को दायर करने से छह महीने पहले है। यह दर्शाता है कि प्रतिवादी थे वादी नंबर 1 की संपत्ति हड़पने के लिए।"

25. वर्तमान मामले में वर्तमान अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों के पिता द्वारा प्रतिवादी-वादी के साथ धोखाधड़ी की गई है, यह स्पष्ट है। इसे साबित करने के लिए प्रतिवादी-वादी को किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता नहीं थी। गवाह झूठ बोल सकते हैं लेकिन हालात झूठ नहीं बोलते. 1984 की नियमित

[19] 2003 (3) PLR 463

द्वितीय अपील संख्या 3174 (ओ एंड एम) -20- इस मामले में, यह अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों के लिए था कि वे धोखाधड़ी, गलत बयानी या अनुचित प्रभाव की अनुपस्थिति को साबित करें क्योंकि उनके पिता एक प्रभावशाली स्थिति में थे, अर्थात प्रतिवादी-वादी। , जो एक अनपढ़ महिला थी। अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों को यह साबित करना था कि लेन-देन में निष्पक्षता बरती गई थी और यह लेन-देन वास्तविक, वास्तविक और प्रामाणिक है।

26. जहां तक अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों के लिए विद्वान वकील की दलील है कि चूंकि पावर ऑफ अटॉर्नी एक पंजीकृत है, कानून प्रथम दृष्टया विलेख के पक्ष में मानता है, जिसे विधिवत निष्पादित किया गया है। उपरोक्त प्राधिकारियों में इस बिंदु पर रखे गए कानूनी प्रस्ताव के संबंध में कोई विवाद नहीं है, जिस पर अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया है। आम तौर पर, एक व्यक्ति, जो धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव आदि के आधार पर लेनदेन की वैधता को चुनौती देता है और अपने प्रतिद्वंद्वी पर बुरे विश्वास का आरोप लगाता है और विशेष रूप से जब लेनदेन पंजीकृत दस्तावेज़ के माध्यम से होता है, तो सबूत का बोझ उस पर होता है और हालांकि, जब ऐसा होता है प्रत्ययी संबंध के अस्तित्व के कारण, उनमें से एक दूसरे पर अनुचित प्रभाव डालने या प्रभुत्व स्थापित करने की स्थिति में है और उससे कोई लाभ लेता है, लेनदेन की सद्भावना साबित करने का बोझ प्रमुख पक्ष पर डाल दिया जाता है।

27. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी-वादी एक विधवा है। मुकदमा दायर करने से 35-36 साल पहले उनके पति की मृत्यु हो गई थी। उनके पति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति उन्हें और उनके पति की एक अन्य विधवा श्रीमती छोटो को विरासत में मिली थी। प्रतिवादी-वादी और श्रीमती छोटू अपने पति की मृत्यु के बाद घर में केवल दो विधवाएँ थीं। उनके पति संत सिंह द्वारा छोड़ी गई जमीन की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इसलिए, उन्हें ज़मीन की देखभाल के लिए किसी पुरुष सदस्य की सहायता की आवश्यकता थी। हरचरण सिंह, संत सिंह की एक और विधवा, श्रीमती छोटो की बहन परसिन कौर के पति हैं। इसलिए, हरचरण सिंह ने संत सिंह की दोनों विधवाओं, यानी श्रीमती शांति और श्रीमती छोटो के साथ रहना शुरू कर दिया और उनका विश्वास जीत लिया। वह उनकी जमीन की देखभाल करता था. दोनों ने जमीन की एक पंजीकृत वसीयत हरचरण सिंह के पक्ष में निष्पादित करने पर सहमति व्यक्त की। इसलिए, हरचरण सिंह ने उन्हें उस उद्देश्य के लिए अपने साथ मनसा चलने के लिए राजी किया। हरचरण सिंह के साथ उनके पिता, जो गांव के नंबरदार थे और उनके चाचा भी थे। वास्तव में उस दिन श्रीमती शांति और श्रीमती छोटू द्वारा हरचरण सिंह के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित और पंजीकृत की गई थी और, हालांकि, उसी समय, हरचरण सिंह ने पावर ऑफ अटॉर्नी पर श्रीमती शांति के अंगूठे का निशान ले लिया और वही प्राप्त कर लिया। साथ ही 1984 की वसीयत के साथ पंजीकृत है। चूंकि हरचरण सिंह की मंशा शुरू से ही गलत थी, इसलिए

उसने उक्त पावर ऑफ अटॉर्नी को इतने वर्षों तक गुप्त रखा। हालाँकि, बाद में जब उन्होंने श्रीमती शांति का विश्वास खो दिया और जब श्रीमती शांति ने उनके पक्ष में निष्पादित वसीयत को रद्द कर दिया और उसके कुछ ही दिनों के भीतर अपने अन्य रिश्तेदार, अर्थात् श्रीमती गुरदेव कौर के पक्ष में एक और वसीयत निष्पादित कर दी। उन्होंने श्रीमती शांति की संपूर्ण संपत्ति का विक्रय पत्र अपने तीन बेटों के पक्ष में निष्पादित कर दिया, जिनमें दो नाबालिग बेटे भी शामिल थे, जिनके पास कोई आय नहीं थी, उनके पक्ष में विक्रय पत्र पंजीकृत करके। इसलिए, इन तथ्यों पर, यह साबित करना वर्तमान अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों और उनके पिता हरचरण सिंह का काम था कि श्रीमती शांति द्वारा हरचरण सिंह के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी का निष्पादन और पंजीकरण एक वास्तविक लेनदेन था और हरचरण सिंह द्वारा बिक्री विलेख का निष्पादन किया गया था। वर्तमान अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों के पक्ष में भी एक उचित लेनदेन था और 36,000/- रुपये का भुगतान वास्तव में हरचरण सिंह द्वारा श्रीमती शांति को किया गया था और, हालांकि, वे इसे साबित करने में विफल रहे हैं।

28. इसलिए, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि श्रीमती शांति द्वारा हरचरण सिंह के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी का निष्पादन उनके साथ की गई धोखाधड़ी का परिणाम है और इसके बाद हरचरण सिंह द्वारा बिक्री विलेख का पंजीकरण किया गया है। उनके बेटों, यानी वर्तमान

अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों का पक्ष भी एक दिखावटी लेनदेन है और इसलिए, प्रतिवादी-वादी उक्त बिक्री से बाध्य नहीं है।

29. इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा इस अपील में उत्पन्न होने वाले कानून के उपरोक्त दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न अपीलकर्ताओं के खिलाफ और प्रतिवादी-वादी के पक्ष में तय किए जाते हैं।

30. मेरी उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, वर्तमान नियमित दूसरी अपील में कोई योग्यता नहीं है। इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

31. हालाँकि, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

ज. ठाकुर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

बिलासपुर यमुनानगर